>

Title: Alleged anomalies in the pay scale of Gramin Dak Sewaks (GDS) of the Department of Posts in the 6th Pay Commission.

**श्री रघुराज सिंह शाक्य (इटावा) :** अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से जी.डी.एस कर्मचारी, जो ग्रामीण क्षेत्रों में पोस्टमैन हैं, उनके बारे में मामला उठाना चाहता हूं। वे पोस्टमैन गांवों की जनता के लिये चिट्ठी और मनीऑडर देने का काम करते हैं। लेकिन उन्हें मात्र वेतन 3500 रुपये प्रतिमाह दिया जाता है। उन लोगों को सेवा में 15 से 20 साल तक हो गये हैं। अब तो यहां तक कर दिया गया है कि इन्हें घंटों के हिसाब से वेतन देने का काम किया गया है। सरकार ने ऐसा कानून बना दिया है कि वे पोस्टआफिस केवल तीन घंटे ही खुला करेंगे। इस हिसाब से उन्हें कितना वेतन मिलेगा? मेरा सरकार से आगृह है कि सरकारी सेवा में कार्यरत कर्मचारियों की सेवा के आधार पर जीडीएस कर्चारियों को वेतन दिया जाये। इन लोगों को आज तक बोनस तक नहीं मिला है। उन्हें भी केन्द्रीय सिविल सेवा के कर्मचारियों के अनुसार बोनस दिया जाये और ग्रामीण क्षेत्र की डाक सेवा में कटौती न की जाये। श्री नटराजमूर्ति समिति द्वारा निर्धारित मानदंड खत्म किये जायें, सीधे सीधे उन्हें खारिज किया जाये। ग्रामीण डाक सेवा कम से कम चार घंटे जरूर खुले।...(व्यवधान)

**अध्यक्ष महोदय :** इतने बड़े स्टेटमेंट के लिये टाइम नहीं है।

**श्री रघुराज सिंह शाक्य (इटावा) :** अध्यक्ष जी, छठे वेतन आयोग द्वारा निर्धारित पे बैंड इनके लिये भी लागू किया जाये और वार्षिक बढ़ोतरी 3 प्रतिशत तय की जाये। मेरा आपके माध्यम से माननीय संचार मंत्री जी अनुरोध है कि इन कर्मचारियों का ध्यान रखा जाये और ग्रामीण क्षेत्रों के लिये डाक संबंधी सभी सुविधायें प्रदान की जाये।[s21]

**श्री देवेन्द्र प्रसाद यादव (झंझारपुर):** अध्यक्ष महोदय, सरकार को रेस्पांस करना चाहिए, यह ग्रामीण डाक सेवकों का मामला है। ये समाज के अंतिम कर्मचारी हैं।

MR. SPEAKER: Mr. Gangwar, I called your name. You should have lost your turn. But you are losing your Deputy Leader. In that consolation, I am permitting. Why are you sending my friend away?